सफलता की कहानी...

समग्र सहकारी विकास परियोजना श्रीगंगानगर

सहकारिता विभाग द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के वित्तीय सहयोग से श्रीगंगानगर जिले में 35 करोड़ 77 लाख रूपये की परियोजना संचालित की जा रही है। 30 सितम्बर, 2016 तक संचालित इस परियोजना हेतु एनसीडीसी द्वारा उपलब्ध कराई जा रही राशि में से 16 करोड़ 19 लाख रु. ऋण, 9 करोड़ 88 लाख रु. हिस्सा राशि एवं 9 करोड़ 70 लाख रु. की राशि अनुदान के रूप में सहकारी संस्थाओं के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। श्रीगंगानगर जिले की समग्र सहकारी विकास परियोजना का योजनाबद्ध क्रियान्वयन का परिणाम यह रहा है कि परियोजना को प्राप्त चतुर्थ वर्ष तक की कुल राशि 32.57 करोड़ रु. में से माह जून, 2015 तक राशि 32.15 करोड़ रूपये की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है।

परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन का परिणाम है कि चतुर्थ वर्ष में जिले की सहकारी संस्थाओं को ठोस वित्तीय आधार व आधारभूत सुविधाएं प्राप्त हुई है। महाप्रबन्धक श्री बलविन्दर सिंह ने परियोजना के योजनाबद्ध क्रियान्वयन व प्रभावी मोनेटरिंग पर जोर दिया जिससे जिले में हुए निर्माण कार्य, फर्नीचर एवं फिक्चर्स, स्टील सैफ तथा कम्प्यूटर एसेसरीज आदि बेहतर गुणवत्ता की होने से समितियों की कार्य क्षमता एवं स्वरूप में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने लगे हैं।

परियोजना का क्रियान्वयन

समितियों का दौरा कर ग्राम सेवा सहकारी समितियों के लिए निर्धारित प्रावधानों एवं समितियों के वास्तविक आवश्यकताओं का आंकलन कर प्रयोजनवार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया गया। इससे समितियों को वास्तविक लाभ प्राप्त हो सका। इसके लिए दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक की सभी 22 शाखाओं के ऋण पर्यवेक्षकों एवं पैक्स व्यवस्थापकों से चर्चा, परियोजना के विकास अधिकारियों, समितियों का विजिट कर संचालक मण्डल के सदस्यों से चर्चा करके वास्तविक आवश्यकता का आकलन कर राशि जारी करने का निर्णय किया गया।

80 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदाम मरम्मत सहायता हेतु चिन्हित किया गया। 115 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में नए गोदाम निर्माण सहायता हेतु चिन्हित किया गया। 140 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के क्षेत्र में उपभोक्ता व्यवसाय वृद्धि की प्रबल संभावनाएं को देखते हुए मिनी सुपर मार्केट निर्माण सहायता हेतु चिन्हित किया गया।

ग्राम सेवा सहकारी समितियों हेतु तिजोरी (40), फर्नीचर (100), काउन्टर (100), करेन्सी चैकिंग मशीन (296) की आवश्यकता को देखते हुए का चयन किया गया।

कृषि यंत्रों के रख रखाव हेतु 50 ग्राम सेवा सहकारी समितियों को कृषि यंत्रों के लिए शैड निर्माण हेतु चयनित किया गया।

जिले की क्रय विक्रय सहकारी समितियों में डिपार्टमेन्टल स्टोर हेतु-5, गोदाम निर्माण हेतु-6, फर्नीचर फिक्चर्स एवं कम्प्यूटर एसेसरीज हेतु-17 समितियों का चयन किया गया। उक्त के अलावा जिला सहकारी उपभोक्ता भण्डार, जिला सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक एवं महिला सहकारी समितियों हेतु आंकलित सम्भावनाओं के आधार पर विभिन्न मदों के अन्तर्गत सहायता उपलब्ध करवाने बाबत चयनित किया गया।

श्रीगंगानगर परियोजना अन्तर्गत 30 जून, 15 तक की सैक्टरवार प्रगति निम्नानुसार रही है :- (राशि लाखों में)

सैक्टर विवरण	प्रावधान (2014-15 तक)	2014-15 तक के प्रावधान के विरूद्ध			
		स्वीकृति		व्यय/रिलीज	
		राशि	प्रावधान पर प्रतिशत	राशि	स्वीकृत पर प्रतिशत
ग्राम सेवा सहकारी समितियों को सहायता	1611.10	1631.60	101	1580.35	97
क्रय विक्रय सहकारी समितियों को सहायता	344.32	378.32	110	352.52	93
अन्य सहकारी संस्थाओं (भण्डार एवं महिला सह. समितियों) को सहायता	45.00	52.00	116	31.00	60
बैंकिंग सहकारी संस्थाओं (श्रीगंगानगर/ रायसिंहनगर पीएलडीबी) को सहायता	116.50	136.50	117	116.50	85
बैंकिंग सहकारी संस्था (दी गंगानगर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0) को सहायता	375.50	435.50	116	383.00	88
डेयरी संघ	399.00	399.00	100	297.00	74
पीआईटी व्यय - प्रशिक्षण	43.00	36.67	85	36.67	100
पीआईटी व्यय - अन्य	321.12	145.84	45	145.84	100
योग	**3255.54**	**3215.43**		**2942.88**	

आई.सी.डी.पी., श्रीगंगानगर
हाकमावाद ग्राम सेवा सहकारी समिति, 100 एम.टी. गोदाम

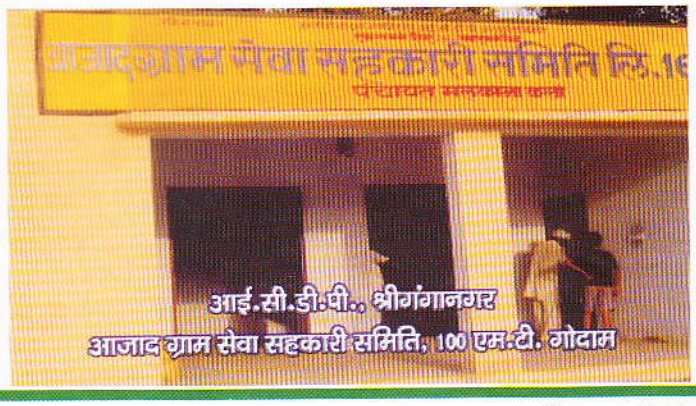

आई.सी.डी.पी., श्रीगंगानगर
आजाद ग्राम सेवा सहकारी समिति, 100 एम.टी. गोदाम

परिसम्पत्तियों का निर्माण

(अ) गोदाम / मिनी सुपर मार्केट निर्माण

109 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100-100 एमटी के नए गोदाम निर्माण का निर्णय किया गया। इनमें से 84 समितियों में गोदाम निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है।

100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में मिनी सुपर मार्केट निर्माण की स्वीकृतियां जारी की गई, जिसमें से 75 समितियों में कार्य पूर्ण हो चुका है।

आई.सी.डी.पी., श्रीगंगानगर
सादुलशहर ग्राम सेवा सहकारी समिति, मिनी सुपर मार्केट

(ब) गोदाम मरम्मत

16 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदाम मरम्मत कार्योमें से 12 समितियों में मरम्मत का काम पूरा हो चुका है।

4 क्रय विक्रय सहकारी समितियों को स्वीकृत 500 एमटी गोदाम पूर्ण हो चुके है। 250 एमटी गोदाम कुल स्वीकृत 6 में से 3 पूर्ण एवं शेष का निर्माण कार्य जारी है।

आई.सी.डी.पी., श्रीगंगानगर
सादुलशहर क्रय विक्रय सहकारी समिति, 500 एम.टी. गोदाम

स्वीकृत 5 डिपार्टमेन्टल स्टोर में से 4 पूर्ण हो चुके है।

(स) डेयरी संघ

परियोजनान्तर्गत प्रावधित राशियों में से आवश्यकतानुरूप मद परिवर्तन करने के फलस्वरूप श्रीगंगानगर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. के पक्ष में मद परिवर्तन डीएलसीसी की बैठक की अनुशंषा के आधार पर सहकारी विभाग तथा एनसीडीसी से स्वीकृति प्राप्त होने पर राशि 399.00 लाख रूपये की स्वीकृतियां जारी की गई है। जिसके अन्तर्गत जिले में घड़साना मुख्यालय पर डेयरी संघ (गंगमूल) का चिलिंग प्लाण्ट निर्माण, सूरतगढ़, पदमपुर एवं घड़साना में निर्माण कार्य एवं नवीनीकरण किये जा रहे हैं।

जनशक्ति विकास एवं प्रशिक्षण

श्रीगंगानगर परियोजना अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिए चतुर्थ वर्ष (2014-15) तक प्रावधित राशि 43.00 लाख रूपये के पेटे दिनांक 30 जून, 2015 तक 36.67 लाख रूपये (85%) राशि व्यय की जा चुकी है। ग्राम सेवा सहकारी समिति की प्रबन्धकारिणी समिति के 2974 सदस्यों को एवं 287 समितियों के साधारण सदस्यों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन कर प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

राईसेम द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के 251 व्यवस्थापकों एवं 139 सहायक कार्मिको को प्रशिक्षण कार्यक्रय आयोजित कर प्रशिक्षण दिया गया।

जिले के 41 सहकारी बंधुओं को पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश के अमृतसर, व्यास, जालंधर, होशियारपुर, चिंतपूर्णी एवं राष्ट्रीय स्तर पर एनसीडीसी सम्मानित पैक्स लाम्बड़ा कांगड़ी एवं महल गहलां का स्टडी टयूर आयोजित करवाया जाकर लाभान्वित किया गया है।

समग्र सहकारी विकास परियोजना श्रीगंगानगर के महाप्रबन्धक श्री बलविन्दर सिंह के नेतृत्व में पी.आई.टी. के टीम भावना से कार्य निष्पादन के फलस्वरूप योजनाबद्ध क्रियान्वयन के प्रयासों का ही परिणाम है कि जिले की सहकारी समितियों में आधारभूत सुविधाओं, गुणवत्तायुक्त परिसंपत्तियों का निर्माण और योजना प्रावधानों का समयबद्ध उपयोग संभव हो पाया है। परियोजना के क्रियान्वयन का लाभ भी क्षेत्र में स्पष्ट दिखाई देने लगा है। जिले की सहकारी संस्थाओं की सक्षमता, आधारभूत सुविधाओं से जिले के काश्तकारों और आम नागरिकों को लाभ मिलने लगा है।